In view of the present grave scarcity situation, I would humbly request the Government of India that they must start Rural Development schemes and other useful projects like construction of roads, ponds, small and check dams etc. for the development of this area, on a war footing base. This would provide employment to the labourers and also help the development of this area. Those farmers who have to get their wells dug deeper, must be given assistance in the form of loans and subsidy. Their outstanding debts may be written off. Action *should be taken on a war-footing* to provide water to this area. Otherwise, the farmers of this part of Gujarat will perish and his cattle would also die.

The Government of India have taken many effective measures to meet the drought situation. The Honourable Prime Minister has also postponed his foreign tours and is paying more attention to monitoring of relief measures. I would request that steps should be taken to avoid the shifting of cattle to Butcher houses.

I am grateful to you, Sir, for providing me an opportunity for expressing my views in this August House.

श्री मीर्जा इर्शाद बेग (गुजरात) : मान्यवर, जो बात राठवा जी ने यहां पर कही है कि बड़ा ही भयंकर सूखा है और सूखे की चपेट में आदिवासी जनता, और पूरे मवेशी आ चुके हैं इसलिये मैं उनकी बात का समर्थन करता हूं ।

REPORTED DECISION TO SHIFT SCOOTER AND TRACTOR FACTORY FROM FATUHA (BIHAR)

श्री राम अवधेश सिंह (बिहार) : माननीय महोदय, सबसे पहले मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर खींचना चाहता हूं कि जो हम लोग विशेष उल्लेख के जरिये इस सदन में समस्या रखते हैं, उस पर सरकार का कोई ध्यान जाता नहीं है मैं तो इस राय का हूं कि इस व्यवस्था को बन्द कर देना चाहिये क्योंकि हम लोग यहां बोलते हैं, जो सत्ता की सर्वोच्च संस्था है और यहां जो सवाल उठाये जायें, उसके बारे में भी सरकार संजीदगी से ध्यान न दे तो सवाल उठाने का कोई अर्थ नहीं होता है । इससे तो जीरो-आवर रहता है, वह ठीक रहता है, उसमें मंत्री लोग भी होते हैं सारे और उसमें तू-तू मैं मैं होती है तो समस्या को समझते हैं... (**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (श्री जगश देसाई) : आप को इसका जवाब देंगे ।

श्री राम अवधेश सिंह : मैं यह बहुत दुखी होकर बोल रहा हूं । ... (**व्यवधान**)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI M. M. JACOB): Sir, the Government takes note of the Special Mentions and hon. Members also get replies in respect of the Special Mentions made by them in the House.

श्री राम अवधेश सिंह : महोदय, मैं ऐसी समस्या की ओर ध्यान खींच रहा हूं, जिसको सरकार ने बनाया और बिगाड़ा । आप जानते हैं, बिहार की आर्थिक स्थिति सारे देश में सबसे खराब है बेरोजगारी के हिसाब से और अन्य स्थिति के हिसाब से । हालांकि 45 फीसदी मिनरल रिसोर्सेज सारे देश की बिहार में हैं, लेकिन हमारे साथ जो खिलवाड़ होता है उसको अब हम बर्दाश्त करने के लिये तैयार नहीं हैं ।

महोदय, एक उदाहरण मैं दे रहा हूं इस विशेष उल्लेख के जरिये कि फतुहा पटना से कोई 50 किलोमीटर पूरबी गंगा के किनारे और बड़ी लाइन के बीच में एक जगह है, वहां 300 एकड़ जमीन अर्जित की गयी फैक्ट्री बनाने के लिये बिहार सरकार के द्वारा । उसमें सारे गांव के करीब एक हजार किसानों की जमीन चली गई, 500 मजदूर थे वह भी बेरोजगार हो गए । कारखाना बना दिया गया, कारखाना काम करने लगा,

स्कूटर फैक्टरी बन गयी, उसमें ट्रैक्टर बनाने के लिये भी सैट बनाए गए। इसके अलावा और भी वहां इंडस्ट्रियल कांपलेक्स बनाए गये हजारों छोटे-छोटे उद्योग धंधे खड़े करने के। इसके बावजूद आज स्थिति उसकी यह है कि कोई यूनिट काम नहीं कर रही और यह जो स्कूटर फैक्टरी है, वहां से उखाड़ कर सरकार दूसरी जगह ले जाना चाहती है, टैक्टर फैक्टरी को दूसरी जगह ले जाना चाहती है। मैं आप से निवेदन करूं, भारत सरकार के उद्योग मंत्री ने सिर्फ आश्वासन ही नहीं दिया था, इस उद्योग के प्रांगण का शिलान्यास 3 सितम्बर, 1974 को टी०ए०पाई० जी ने किया था। इसके अलावा जब भी कोई भारत सरकार का उद्योग मंत्री जाता है, कोई बड़ा मंत्री जाता है बिहार, तो कहता है, कहता रहा है कि फतुहा को एक नए इंडस्ट्रियल कांपलेक्स में और शानदार कांपलेक्स में बदला जाय। लेकिन आज स्थिति यह है कि अब वहां से कारखाने उखड़ कर दूसरी जगह जा रहे हैं और दूसरे कारखानों की मशीनों में जंग लग रही है।

महोदय, सबसे बड़ा अन्याय शुरू में यही हुआ कि यह आश्वासन था, जिन किसानों की जमीन ली गयी, वह पथरीली जमीन नहीं थी, जंगल की जमीन नहीं थी, आप जाकर जांच करेंगे तो पता चलेगा ऐसी जमीन थी, जो साल में तीन फसल देती थी, और कम से कम वहां एक एकड़ में किसान आठ से दस हजार रुपया फसल से पैदा करता था। ऐसी अच्छी जमीन को लेकर बर्बाद कर दिया गया, सड़क, मकान सब बना दिया और अब कहते हैं कि यहां से उठाकर ले जायेंगे। तो हम चाहते हैं कि सरकार इस पर ध्यान दे। साथ ही मैं यह कहना चाहता हूं कि ऐसा कह कर टालने से काम नहीं चलेगा कि सिक इंडस्ट्री है, सिक इंडस्ट्री तो कुछ नहीं है, अभी तो खड़ा ही किया है। कोई उद्योगपति इंडीविजुअल कैपटलिस्ट कारखाना खड़ा करे, जैसे आप कह देते हो कहीं शुगर मिल के बारे में, कहीं जूट मिल के बारे में; किंतु जूट मिल के बारे में वैसा जवाब देने से काम नहीं चलेगा। महोदय, मैं आप के माध्यम से केन्द्र सरकार को चेतावनी के रूप में कहना चाहता हूं कि अब बिहार ज्यादा बर्दाश्त नहीं करेगा। यह बिहार सरकार और भारत सरकार का मामला है। बिहार सरकार ने काम्पलैक्स खोलकर जमीन ली पब्लिक एंटरप्राइजेज के रूप में उसको खड़ा किया और अब उसको कालैप्स करा रहे हैं। हम इसमें दूसरे को दोष नहीं दे सकते कि ये फलां कैपटलिस्ट का दोष है। दोष बिहार सरकार और भारत सरकार का है, इसलिये मैं जो यह आपके समक्ष निवेदन कर रहा हूं इसे प्रधान मंत्री से लेकर वित्त मंत्री, उद्योग मंत्री सभी को इसकी कटिंग भेजनी चाहिये। मैं हमारे पार्लियामेंट एफेअर्स मंत्री महोदय, जो यहां बैठे हैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि यह हम लोगों के लिये जीवन-मरण का सवाल है। वहां के 20 हजार लोगों के एम्प्लायमेंट का सवाल है। इसके अलावा जिन किसानों की जमीन ली गई, वे भी बेरोजगार हैं। किसी तरह से वहां धंधा चलने वाला नहीं और न चल रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि हमारी इसमें कुछ मांगें हैं, उन पर तत्काल ध्यान दिया जाय—(1) स्कूटर फैक्टरी तथा ट्रैक्टर फैक्टरी को उत्पादन में लगाया जाय। उसको ट्रांसफर न किया जाय। मशीन उखाड़कर दूसरी जगह न लगायी जाय, (2) कर्मचारियों का स्थानांतरण तथा मशीनों का बाहर भेजना जल्द बन्द किया जाय, (3) विस्थापित किसान और मजदूर परिवार के सदस्यों को योग्यता के अनुसार नौकरी दी जाय और (4) फैक्टरी चलाने हेतु योग्य अफसरों को वहां पदस्थ किया जाय।

महोदय, इस मांग और सुझाव के साथ मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। आपने समय दिया, धन्यवाद।

श्री धीरेन्द्र वर्मा (बिहार) : महोदय, आप की आज्ञा से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे साथी ने जो यह प्रश्न उठाया है, मैं इसका समर्थन करता हूं। इसमें किसान तो बहुत बड़ी तादाद में बर्बाद हो ही चुका है। लोग भी बेकार हो जायेंगे, इसलिये सरकार को इस पर पुनः विचार करना चाहिये कि

वहां के गरीब लोगों के हित में उसको वहां से न हटाया जाय ।

श्री अश्विनी कुमार (बिहार) : उपसभाध्यक्ष महोदय, यह फतुहा इंडस्ट्रियल कांपलैक्स की जो समस्यायें हैं, वह केन्द्रीय सरकार के कारनामे हैं जिनके कारण वह फैक्ट्रियां बैठती जा रही हैं। अभी माननीय सदस्य ने स्कूटर फैक्टरी, ट्रैक्टर फैक्टरी का नाम लिया। वहां पर यह एन्टरप्रेन्योर्स ने स्पोर्टस कांपलैक्स खड़ा किया जो भारत में पंजाब के अलावा कहीं नहीं है। स्पोर्टस कांपलैक्स जब बना तो तय हुआ था कि हमारी जो स्पोर्ट काउन्सिल है, वह उनका माल विदेशों में भेजेगी। मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि स्पोर्ट काउन्सिल ने फतुहा स्पोर्ट कांपलैक्स के सामान को भेजने का कोई प्रयास नहीं किया स्टेट बैंक आफ इंडिया ने उनको सीड मनी दी। वर्किंग कैपिटल देने के लिये एस०बी० आई० में तीन-तीन साल तक दौड़ाया है और कई लोगों को बर्बाद कर दिया है मैं आप के माध्यम से केन्द्रीय सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि उनकी जो एजेंसीज हैं जिसके कारण गड़बड़ी हो रही है उस ओर ध्यान दिया जाय फतुहा कांपलैक्स समाप्त होने जा रहा है इसके पहले बिहार के तीन बड़े कांपलैक्स रोहतास इंडस्ट्रीज, अशोक पेपर मिल और फतुहा फैक्ट्रीज बंद हो गयी हैं। यह केन्द्र सरकार और बिहार सरकार के बीच में खेल चल रहा है, लेकिन वे प्रारंभ नहीं हो रही हैं। बिहार में औद्योगीकरण की दृष्टि से जो अशांति पैदा हो रही है, उसको ठीक करने के लिये अविलम्ब केन्द्रीय सरकार ध्यान दे, यह मेरा आप से निवेदन है।

NEED TO PROVIDE CONSUMPTION LOANS TO MARGINAL FARMERS AND LANDLESS RURAL LABOURERS

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL (Punjab): Mr. Vice-Chairman, Sir, I rise to make a special mention on the urgent need to devise an appropriate statutory mechanism for providing consumption loans to marginal farmers and landless rural labourers. I am indeed very grateful to you for affording me this opportunity to make this special mention which I avail of with a feeling of consternation, a feeling which emanates from, if I may say so, a callous reply to one of my questions the other day. My Unstarred Question No. 1468 dated 7th August, asked *inter alia*—whether any steps are envisaged for protecting the marginal farmers and landless rural labour from the burden of exorbitant interest paid in distress to private moneylenders and whether there is any plan to provide them help in kind during the lean periods by creation of separate societies for the specific purpose—and I repeat my feeling of disgust when I say that the answer to these questions is simply: "Do not arise". Sir, for the last one week I was really hoping that the Government would come forth with a correction to this reply, but I am sorry to say that I do not know what the rank of the officer is, who prepared the answer to this question unmindful of the Government's policy. I could understand if the answer were to say, "because of constraint of resources, it is not possible", but the present answer is that the question does not arise. After having waited for a week to elicit some correction to this answer, I am constrained to rise to make a Special Mention here.

When I do so, I must also in all fairness to the Government acknowledge gratefully the interest which the Prime Minister takes to ameliorate the lot of the weaker sections of society, an interest which he holds very close to his heart. It was this only which impelled the hon. Prime Minister to direct the payment of immediate compensation to those farmers whose crops had been destroyed recently in Punjab and it was only because of his personal interest in the matter that timely assistance in the form of compensation was